

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के बजट में कोई कटौती नहीं की जाएगी। आज शिमला में उच्च शिक्षा में सुधारों पर आयोजित प्रधानाचार्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए सरकार ने कई पहल की है और महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की तर्ज पर कॉलेज रैंकिंग प्रणाली भी लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने सभी शीर्ष रैंकिंग वाले कॉलेजों को सम्मानित किया और प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कॉलेजों में न्यू एज के पाठ्यक्रम और अतिरिक्त भाषा कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए ताकि विद्यार्थियों की रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढ़ सके। उन्होंने कहा कि सीबीएसई स्कूलों की शुरुआत के बाद इनमें छात्रों के दाखिलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और अगले दो महीनों में इन स्कूलों में आवश्यकतानुसार सभी शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

विधानसभा सत्र

प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण कल 18 मार्च से शुरू होगा जो 2 अप्रैल तक चलेगा। 21 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठनिया ने शिमला में बताया कि बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और चर्चा के साथ होगी। उन्होंने बताया कि 18 से 20 मार्च तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी जबकि 20 मार्च को मुख्यमंत्री चर्चा का जवाब देंगे और सत्र के दूसरे चरण में कुल 13 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि अभी तक कुल 8 सौ 84 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 6 सौ 65 तारांकित और एक सौ 69 अतारांकित हैं। सत्र के दौरान नियम 62 के अंतर्गत 8, नियम 102 के तहत 3 और नियम 130 के तहत 5 विषयों पर सदन में चर्चा होगी।

जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि 18 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है और विपक्ष सदन में जनहित के सभी मुद्दों को उठाएगा। शिमला में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, बिगड़ती आर्थिक स्थिति और ठप पड़े विकास कार्य जैसे कई गंभीर मुद्दे हैं, जिन पर विपक्ष ने नोटिस दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं और वह लगातार सदन को गुमराह कर रही है। नेता प्रतिपक्ष ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस विभाग को सूचना का अधिकार के दायरे से बाहर करने के निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने सरकारी संस्थानों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि कैबिनेट बैंक वापिस लेने की प्रक्रिया महज जनता की आंखों में धूल झाँकने का एक असफल प्रयास है।

कैबिनेट बैंक

राज्य सरकार ने विभिन्न प्राधिकरणों को दिए गए 'कैबिनेट बैंक' के दर्जे को वापस लेने का निर्णय लिया है। इसमें बोर्ड, निगम और आयोगों के चेयरमैन, वाईस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और प्रधान सलाहकार व राजनीतिक सलाहकार शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यह निर्णय व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है और आने वाले समय में कई परिवर्तन किए जाएंगे।

नलवाड़ी मेला

बिलासपुर ज़िला के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक एक सौ 37 वर्ष पुराने राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले का आज नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने खूंटी गाड़कर विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर से आरंभ हुई भव्य शोभायात्रा का नेतृत्व किया और लुहणू मैदान में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। धर्माणी ने कहा कि वर्षों पहले इस नलवाड़ी मेले में ग्रामीण अपने उत्पादों की बिक्री और पशुधन की खरीद-फरोख्त करते थे, लेकिन वर्तमान में ये मेला सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख मंच बन चुका है।

पर्यटक

भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल के साउथ पोर्टल के समीप फंसे सभी 3 सौ 20 वाहनों को सुरक्षित निकालकर मनाली की ओर रवाना किया गया है। कुल्लू के उपायुक्त अनुराग चंद शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ज़िला प्रशासन, बी.आर.ओ., पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के समन्वय से ये राहत व बचाव कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। उपायुक्त ने बताया कि अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से साउथ पोर्टल की ओर वाहनों को आने की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने वाहन चालकों व लोगों से यात्रा के दौरान मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है।
